RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 041
दि. 13.11.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.
Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

वर्दी वाला डॉक्टर जिसने आतंकियों की साजिश नाकाम की कैसे डॉ. जीवी संदीप ने देश को बड़ा हादसा होने से बचाया

(जीएनएस)। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद देश में सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता और सतर्कता पर फिर से ध्यान गया है। इस मामले में कई खुलासे हुए हैं, जिनमें सामने आया कि गिरफ्तार किए गए आतंकी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे। इस साजिश को नाकाम करने में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. जीवी संदीप चक्रवर्ती का प्रमुख योगदान रहा।

17 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के नौगाम क्षेत्र में उर्दू में पोस्टर लगाए गए, जिन पर जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य कमांडर हंजला भाई के हस्ताक्षर थे। पहली नजर में ये पोस्टर सामान्य दिख रहे थे, लेकिन श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. जीवी संदीप ने पोस्टर में छिपे खतरे को तुरंत भांप लिया। उनके नेतृत्व और सतर्कता ने एक बड़े आतंकवादी नेटवर्क की पहचान और उसके संचालन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। सीसीटीवी फुटेज और अन्य खुफिया जांच से तीन संदिग्धों की पहचान हुई, जिन्होंने पहले भी कश्मीर में उपद्रव किया था। इस अभियान में कई कश्मीरी डॉक्टरों और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान 2,900

किलोग्राम विस्फोटक, बम बनाने का सामग्री और राइफलें बरामद की गईं। 10 नवंबर के धमाके के बाद की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि डॉ. जीवी संदीप की सूझबूझ और सक्रिय नेतृत्व ने कई नागरिकों की जान बचाई।

डॉ. जीवी संदीप का जन्म आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक जनसेवा में समर्पित परिवार में हुआ। उनके पिता सरकारी अस्पताल में कार्यरत थे और मां स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी थीं। संदीप ने कुरनूल मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा की पढ़ाई की और 2014 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। उनकी जम्मू-कश्मीर में तैनाती उच्च जोखिम और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही। 21 अप्रैल 2025 को उन्होंने श्रीनगर के एसएसपी का पदभार संभाला, जो कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण पोस्टिंग में से एक है।

छोटी-छोटी चेतावनियों में भी बड़ा संदेश छिपा होता है, यह सोच डॉ. संदीप की कार्यप्रणाली की पहचान है। उन्होंने जैश के पोस्टरों के बाद मौलवी इरफ़ान अहमद को गिरफ्तार किया, जिससे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। फरीदाबाद और अन्य जगहों पर आम नागरिक बनकर कार्रवाई कर कई आतंकी डॉक्टरों को पकड़ा गया। श्रीनगर, फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया। कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल, अदील अहमद और डॉ. शाहीन सईद इस कार्रवाई में शामिल पाए गए।

साहस और रणनीतिक सोच के लिए डॉ. जीवी संदीप को छह बार राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक और चार बार जम्मू-कश्मीर पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया जा चुका है। उनके योगदान ने यह साबित किया कि एक सतर्क, कुशल और दूरदर्शी अधिकारी किस तरह देश की सुरक्षा में बड़ा फर्क ला सकता है। डॉ. संदीप की सूझबूझ और अथक प्रयासों ने कई बड़े हादसों को टालकर देशवासियों की जान बचाई और आतंकियों की योजनाओं को धराशायी किया।

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर गंभीर आरोपों की स्थिति में पद से हटाने से जुड़ा 130वां संविधान संशोधन विधेयक अब संयुक्त संसदीय समिति के पास

(जीएनएस)। नई दिल्ली/मुंबई। देश के संवैधानिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव लाने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए संसद की एक संयुक्त समिति गठित की गई है। यह समिति उस प्रावधान की जांच करेगी जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाया जा सकेगा। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी को इस समिति की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, समिति में कुल 31 सदस्य होंगे, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। इस समिति में प्रमुख रूप से भाजपा की अपराजिता सारंगी, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, हरसिमरत कौर बादल, विष्णु दयाल राम, और कांग्रेस से सुप्रिया सुले शामिल हैं। साथ ही प्रसिद्ध वकील और राज्यसभा सदस्य उज्जवल निकम, पूर्व पुलिस अधिकारी बृजलाल तथा समाजसेवी सुधा मूर्ति को भी इसमें शामिल किया गया है। गौरतलब है कि यह वही तीन विधेयक हैं — संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 — जिन्हें गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किया था। उस समय विपक्षी दलों के विरोध और हंगामे के बीच इन विधेयकों को व्यापक समीक्षा के लिए संयुक्त समिति को भेजने का फैसला लिया गया था।

विपक्षी दलों में खासकर कांग्रेस ने इस समिति से दूरी बनाए रखी है, हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस का मानना है कि यह संशोधन कार्यपालिका पर नियंत्रण के बहाने राजनीतिक लाभ उठाने का उपकरण बन सकता है, इसलिए वह इसकी प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहती। संयुक्त समिति अब इन विधेयकों के प्रत्येक प्रावधान का विश्लेषण करेगी, जिसमें सबसे प्रमुख बिंदु यह होगा कि किसी जनप्रतिनिधि पर आरोप लगने और हिरासत में रहने की स्थिति में लोकतांत्रिक जिम्मेदारी और प्रशासनिक स्थिरता के बीच संतुलन कैसे कायम किया जाए। समिति से अपेक्षा की जा रही है कि वह अगले सत्र तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद इन विधेयकों पर संसद में फिर से चर्चा होगी।

राजनीतिक गलियारों में इस संशोधन को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां सत्तारूढ़ दल इसे 'पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में ऐतिहासिक कदम' बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे 'राजनीतिक हथियार' करार दे रहा है। आने वाले महीनों में समिति की रिपोर्ट और संसद में उस पर होने वाली बहस यह तय करेगी कि यह प्रस्तावित संशोधन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नई इबारत लिखेगा या विवादों का नया अध्याय खोलेगा।

पीरियड्स के दौरान महिलाओं की गरिमा की रक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, हरियाणा की शर्मनाक घटना बनी वजह

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में महिलाओं की गरिमा और निजता से जुड़े एक गंभीर मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल के माध्यम से एक याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में पीरियड्स के दौरान महिलाओं के साथ किया जा रहा व्यवहार उनके सम्मान, शारीरिक स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

इस याचिका में हरियाणा की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (एमडीयू) रोहतक की एक चौंकाने वाली घटना का जिक्र किया गया है, जिसमें चार महिला कर्मचारियों से कथित रूप से उनके पीरियड्स का सबूत मांगा गया। इतना ही नहीं, आरोप है कि इन महिलाओं के कपड़े उतरवाकर सैनिटरी पैड की फोटो ली गई ताकि यह "साबित" किया जा सके कि वे मासिक धर्म में हैं। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया था और आरोपी सुपरवाइजर को तत्काल निलंबित कर दिया गया था।

महिलाओं की गरिमा पर हमला बताया गया

याचिका में कहा गया है कि यह घटना केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है। देश के कई हिस्सों में स्कूलों, कॉलेजों और दफ्तरों में महिलाओं को उनके पीरियड्स के समय शर्मिंदा किया जाता है, उनसे असंवेदनशील सवाल पूछे जाते हैं या उन्हें अपमानजनक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसे मामलों में महिलाओं की गरिमा, निजता और सम्मान से जुड़े संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित हैं।

याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि केंद्र और हरियाणा सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वे इस घटना की स्वतंत्र जांच कराएं और ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए पूरे देश में ठोस दिशानिर्देश तैयार करें। इनमें यह तय किया जाए कि कार्यस्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर पीरियड्स के दौरान महिलाओं को किन सुविधाओं का अधिकार हो, शिकायत कहां और कैसे दर्ज की जाए तथा उसकी निगरानी कौन करे।

पहले भी सामने आ चुकी हैं शर्मनाक घटनाएं

इस याचिका में 2017 से लेकर 2025 तक हुई कई घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश की उस घटना का जिक्र है, जहां 70 लड़कियों को उनके पीरियड्स की जांच के नाम पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया था। इसी तरह गुजरात में 2020 में एक कॉलेज में छात्राओं से अपमानजनक तरीके से पीरियड्स का सबूत मांगा गया था, जबकि 2025 में महाराष्ट्र में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी।

महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों पर बहस तेज

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला न केवल मानवाधिकारों से जुड़ा है, बल्कि यह देश में महिलाओं की गरिमा के प्रति सामाजिक सोच पर भी सवाल खड़ा करता है। इस याचिका से उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर ऐतिहासिक दिशानिर्देश जारी कर सकता है, जिससे कार्यस्थलों और शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की निजता और गरिमा की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि पीरियड्स को अब भी समाज में टैबू की तरह देखा जाता है और यही सोच ऐसे अमानवीय व्यवहार को जन्म देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ठोस दिशा-निर्देश जारी करता है, तो यह महिलाओं के सम्मान और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

रूस ने जापानी अधिकारियों, प्रोफेसरों और पत्रकारों पर लगाया प्रवेश प्रतिबंध, दोनों देशों के संबंधों में बढ़ा तनाव

(जीएनएस)। मास्को। रूस और जापान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे राजनयिक रिश्तों में मंगलवार को एक नई खटास आ गई जब रूस ने 30 जापानी नागरिकों के अपने देश में प्रवेश पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया। रूस ने यह कदम जापान द्वारा लगाए गए रूस-विरोधी प्रतिबंधों के जवाब में उठाया है। रूसी सरकारी संवाद एजेंसी 'तास' के अनुसार, रूस के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि "यूक्रेन में चल रहे विशेष सैन्य अभियान को लेकर जापान द्वारा लगाए गए तथाकथित प्रतिबंधों और रूस-विरोधी गतिविधियों के कारण, 30 जापानी नागरिकों को हमारे देश में प्रवेश से अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है।" यह सूची रूस के विदेश मंत्रालय द्वारा औपचारिक रूप से जारी कर दी गई है। इस सूची में जापान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तोशीहिरो किटामुरा का नाम सबसे प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा जापान की कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, राजनीतिक विश्लेषक, रक्षा विशेषज्ञ और प्रमुख मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों को भी इस प्रतिबंध सूची में जगह दी गई है। रूस का कहना है कि इन लोगों ने सार्वजनिक रूप से रूस के खिलाफ बयान दिए, यूक्रेन को समर्थन देने वाले अभियानों में भाग लिया और जापान सरकार की रूस-विरोधी नीतियों को बढ़ावा दिया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि जापान सरकार ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के दबाव में आकर रूस के खिलाफ एक "शत्रुतापूर्ण रुख" अपनाया है। मंत्रालय के अनुसार, जापान द्वारा लगाए गए आर्थिक और व्यक्तिगत प्रतिबंध रूस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत के बाद से जापान लगातार पश्चिमी देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ आर्थिक, व्यापारिक और वित्तीय प्रतिबंध लागू कर रहा है। सितंबर 2025 में जापान ने अपने नए प्रतिबंधों की सूची जारी की थी, जिसमें कई रूसी कंपनियों, बैंकों और सरकारी अधिकारियों को शामिल किया गया था। इन प्रतिबंधों में संपत्ति फ्रीज करना, लेनदेन पर रोक लगाना और निर्यात पर नियंत्रण जैसे प्रावधान थे। रूस ने इस कार्रवाई को अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताया है और कहा है कि जापान अब "वास्तव में पश्चिमी नीति का अनुयायी" बन गया है।

मॉस्को स्थित जापान में रूस के राजदूत निकोले नोज़द्रेव ने तास को दिए एक बयान में कहा, "जापान ने अपने एक प्रमुख पड़ोसी के साथ संबंध तोड़ने का निर्णय ले लिया है। वह यह सोचता है कि पश्चिम के रूस-विरोधी अभियान में शामिल होकर उसे आर्थिक या रणनीतिक लाभ मिलेगा, लेकिन यह उसकी भूल है। रूस अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा।"

विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम दोनों देशों के बीच पहले से कमजोर हो चुके संबंधों को और ठंडा कर देगा। जापान और रूस के बीच वर्षों से चल रहा कुरील द्वीप विवाद पहले ही राजनयिक बातचीत को प्रभावित कर चुका है। अब यूक्रेन युद्ध के बाद से जापान का रूस-विरोधी रुख और अधिक स्पष्ट हो गया है।

जापानी सरकार ने अब तक रूस के इस नए प्रतिबंध पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन टोक्यो के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि जापान "अपनी विदेश नीति को पश्चिमी सहयोगियों के अनुरूप" ही रखेगा।

नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी अमेरिका की यात्रा पर रवाना, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग होगा और मज़बूत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच सामरिक समुद्री संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी सोमवार को अमेरिका की छह दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए। यह यात्रा 12 से 17 नवंबर तक चलेगी, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल, रणनीतिक सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझे हितों की रक्षा को और मज़बूत करना है। एडमिरल त्रिपाठी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और वैश्विक समुद्री सुरक्षा का संतुलन लगातार चुनौती के दौर से गुजर रहा है। भारत और अमेरिका दोनों इस क्षेत्र में स्वतंत्र और खुले समुद्री मार्गों को बनाए रखने के पक्षधर हैं, और यही साझा दृष्टिकोण दोनों देशों को रणनीतिक साझेदार बनाता है। सूत्रों के अनुसार, एडमिरल त्रिपाठी अमेरिका में अपने समकक्ष वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों के साथ कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। वे अमेरिकी हिंद-प्रशांत कमान (INDOPACOM) के कमांडर एडमिरल सैमुअल जे. पापारो, अमेरिकी प्रशांत बेड़े (PACFLT) के कमांडर एडमिरल स्टीफन टी. कोहलर तथा पेंटागन के शीर्ष रक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में भारत-अमेरिका नौसेनाओं के बीच परिचालनिक सहयोग, समुद्री क्षेत्र में सूचना साझाकरण, और संयुक्त मिशनों की समन्वय प्रक्रिया पर चर्चा होगी। जानकारी के अनुसार, एडमिरल त्रिपाठी अमेरिकी नौसेना के कई प्रमुख नौसैनिक अड्डों और प्रशिक्षण संस्थानों का भी दौरा करेंगे, जहां उन्हें नवीनतम नौसैनिक तकनीक, उन्नत हथियार प्रणालियों और सामरिक प्रशिक्षण ढांचे का प्रत्यक्ष अवलोकन करने का अवसर मिलेगा। इन दौरों का उद्देश्य भारतीय नौसेना की क्षमताओं को आधुनिक तकनीकी दृष्टिकोण से सशक्त बनाना और द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों के स्तर को और ऊँचा उठाना है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ वर्षों में नौसैनिक सहयोग कई गुना बढ़ा है। दोनों देश "मालाबार" जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में एक-दूसरे की क्षमताओं को साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही क्वाड समूह (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) की बैठकों में भी हिंद-प्रशांत सुरक्षा पर गहन संवाद होता है, जिसका केंद्र बिंदु चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता को संतुलित करना है।

नौसेना प्रवक्ता के अनुसार, एडमिरल त्रिपाठी की यात्रा से "दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी भरोसा और समझ और गहरी होगी। यह यात्रा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन, समुद्री व्यापार की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

भारत ने हाल के वर्षों में समुद्री क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की मौजूदगी बढ़ी है और अमेरिका सहित अन्य मित्र देशों के साथ संयुक्त अभ्यासों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

अमेरिकी रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि भारत-अमेरिका नौसेना सहयोग केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दोनों देश समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, समुद्री डकैती रोकने और प्राकृतिक आपदाओं के समय मानवीय सहायता अभियानों में भी साथ काम कर रहे हैं।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

सड़क दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त

विकास के नाम पर हमने सरपट वाहन दौड़ने वाली सड़कें तो बना दी, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया कि यात्रा दुर्घटनाओं से निरापद कैसे रहे। यह हृदय विदारक होता है कि सड़कों के निर्माण में तकनीकी खामियों, ट्रकों की अराजकता तथा राजमार्ग के अवरोधों के चलते परिवार के परिवार असमय काल कवलित हो जाते हैं। तंत्र की चतुराई ये होती है कि मुआवजे और दुर्घटना की फौरी जांच की घोषणा तो कर दी जाती है लेकिन सड़क दुर्घटना के मूल कारणों की तह तक नहीं पहुंचा जाता है। इन हादसों की जवाबदेही तय नहीं की जाती। आए दिन खबर आती है कि तेज गति से आता कोई वाहन सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया और अनेक निर्दोष लोगों की मौत हो गई। इस संकट की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फलोदी इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से दो सप्ताह में दुर्घटना के कारणों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस भीषण दुर्घटना के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिए हैं। दरअसल, इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हादसे की वजह सड़क के किनारे गलत ढंग से खड़ा ट्रक बना। जिससे यात्रियों से भरा तेज गति से आता एक टेम्पो ट्रेवलर टकरा गया। हादसा इतना भीषण था कि इसमें चार बच्चों तथा दस महिलाओं समेत पंद्रह लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल भी हुए। आमतौर पर किसी भी बड़े हादसे में शिकार हुए यात्रियों की संख्या का ही जिक्र होता है और सरकार मुआवजे की घोषणा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। अधिक से अधिक हमारे विमर्श का मुद्दा यह होता है कि दोषी कौन था? कौन सा ड्राइवर लापरवाही से वाहन चला रहा था, वह नशे में था या उसे नींद की झपकी लग गई। या फिर वाहन में तकनीकी खामी की वजह से हादसा हुआ।

लेकिन वास्तव में हम उन तकनीकी व वास्तविक खामियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो दुर्घटना का कारण बनती हैं। एक ओर जहां सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा की गई चूक होती हैं, वहीं सड़कों के किनारे बेतरतीब बने ढाबे भी होते हैं, जहां अकसर ट्रक चालक अपने वाहन गलत ढंग से खड़े कर देते हैं। लेकिन हर हादसे में कहीं न कहीं ऐसे कारण जरूर होते हैं, जो दुर्घटना की तात्कालिक वजह बनते हैं। लेकिन अकसर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कारक को अनदेखा करने की वजह से भविष्य में ऐसी ही दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति होने की आशंका बलवती होती है। यह विडंबना ही है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जगह-जगह टोल संग्रह केंद्रों के जरिये टैक्स तो खूब वसूले जाते हैं, लेकिन राजमार्गों को दुर्घटनाओं से निरापद बनाने के लिये गंभीर प्रयास नहीं होते। कुकरमुत्तों की तरह सड़कों का अतिक्रमण करते ढाबों पर लगाम नहीं लगायी जाती। गंभीरता से पड़ताल नहीं होती है कि क्या सड़क निर्माण में ठेकेदार ने सभी तकनीकी मानकों का पालन किया है? निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की जवाबदेही बनती है कि राजमार्गों को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिये नियमित जांच-पड़ताल की जाती रहे। ताकि निर्दोष लोगों के बेमौत मरने का सिलसिला खत्म हो सके। इन विभागों व मंत्रालयों का जिम्मा सिर्फ टोल वसूलना ही नहीं है बल्कि सड़कों को सुरक्षित बनाना भी इनकी जवाबदेही है। निश्चित रूप से सड़क के निर्माण की गुणवत्ता तथा उसे दुर्घटना मुक्त बनाने के लिये उच्च सुरक्षा मानकों का क्रियान्वयन भी उतना जरूरी है। इसके अलावा सख्त कानून व निगरानी के जरिये ट्रकों को सड़क के किनारे खड़े करने पर रोक लगायी जाए। देश में सैकड़ों लोगों की मौत सड़क के किनारे गलत तरीके से खड़े ट्रक से वाहनों के टकराने से होती है, लेकिन दोषी ट्रक चालक को कड़ी सजा नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों को भी गति सीमा में रहने तथा अन्य सावधानियों का सख्ती से पालन करना चाहिए। सरकारों का दायित्व भी बनता है कि राजमार्गों पर रफ्तार की सीमा के नियमन के साथ बाधामुक्त सफर भी सुनिश्चित करें।

विकास और जलवायु परिवर्तन के बीच संतुलन जरूरी

> “रिपोर्ट ने जो सुझाव दिए हैं उनमें राज्य जलवायु लचीलापन कोष, हर जिले में जलवायु जोखिम मानचित्रण, हरित उद्योगों और कृषि-वानिकी को बढ़ावा तथा डिजिटल तकनीक द्वारा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली हैं।

भारत की विकास यात्रा आज दो विरोधी धाराओं के बीच खड़ी है—एक ओर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण में प्रगति और दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली विनाशकारी असुरक्षा। केरल, तमिलनाडु, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य, जो मानव विकास सूचकांक में देश का नेतृत्व करते हैं, अब इस द्वंद्व के केंद्र में हैं। ऐसे समय में, हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ तैयार किया गया है, पूरे भारत के लिए एक दिशासूचक दस्तावेज़ के रूप में उभरकर सामने आई है। यह ऐसी पहली रिपोर्ट है, जिसमें मानव विकास को जलवायु जोखिमों के साथ जोड़ा गया है।

हिमाचल ने का मानव विकास सूचकांक 0.78 है, जो राष्ट्रीय औसत 0.63 से अधिक है, लेकिन अब जलवायु संकट इस प्रगति के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है, जो न केवल हिमाचल प्रदेश, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। हिमाचल का अनुभव अकेला नहीं है। केरल का सामाजिक मॉडल बाढ़ और तटीय क्षरण से जूझ रहा है। तमिलनाडु के औद्योगिक नगरों पर जलसंकट और प्रदूषण का दबाव है। ओडिशा और गुजरात राज्यों को चक्रवातों और हीटवेव से भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड और सिक्किम पर्यटन, जलविद्युत और पर्यावरण संतुलन के बीच झूल रहे हैं। यह सब मिलकर संकेत देते हैं कि भारत का अगला विकास अध्याय केवल आर्थिक नहीं बल्कि जलवायु-सक्षम मानव विकास का होना चाहिए।

रिपोर्ट में, हिमाचल की बुजुर्ग होती आबादी, युवाओं का पलायन, जल संकट और आपदाएं—को चिन्हित किया गया है। देश-भर में बुजुर्गों का प्रतिशत 2050 तक 20 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, जिससे वृद्ध स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा का दबाव बढ़ेगा। खेती की घटती आय और सीमित औद्योगिकीकरण युवाओं को गांवों से शहरों की ओर धकेल रहा है। यह पलायन, हिमाचल की तरह, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर बना रहा है। वहीं, पंजाब के सूखते भूमिगत जल, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की सूखे से जूझती जमीन, गंगा बेसिन का प्रदूषण और हिमाचल की सूखती धाराएं—सभी एक ही कहानी कहते हैं। इसके लिए समाधान स्थानीय स्तर पर होने चाहिए।

शहरी दबाव के चलते जहां शिमला, सोलन और मंडी जैसे शहर कचरा, ट्रैफिक और आवासीय दबाव से त्रस्त हैं, वहीं बेंगलुरु, पुणे और गुवाहाटी जैसे महानगर भी इसी असंतुलन के शिकार हैं। इसके लिए एकीकृत शहरी नियोजन और पर्यावरण-संवेदनशील निर्माण नीति की जरूरत है।

पिछले पांच वर्षों में हिमाचल को आपदाओं से लगभग 46,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4 प्रतिशत है। वर्ष 2023 में भारत-भर में 2,800 से अधिक लोगों की मृत्यु और 1.4 लाख करोड़ की क्षति जलवायु-जनित घटनाओं से हुई। हिमाचल का 75,000 करोड़ रुपये का ऋण बोझ यह दर्शाता है कि छोटे राज्यों की वित्तीय स्थिति कितनी नाजुक है। रिपोर्ट ने ग्रीन बॉन्ड, आपदा बीमा और कार्बन क्रेडिट जैसे उपाय सुझाए हैं। गुजरात ने पहले ही हरित ऊर्जा बॉन्ड जारी किए हैं और ओडिशा ने अपने बजट में जलवायु व्यय को शामिल किया है। हिमाचल का यह दृष्टिकोण बताता है कि हर राज्य यदि अपनी वित्तीय नीति को हरित और लचीला बनाए तो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन संभव है।

हिमाचल की सबसे बड़ी ताकत उसका सामाजिक समावेशन है। 58 प्रतिशत पंचायत सीटें महिलाओं के पास हैं, जिससे नीतिगत निर्णयों में लैंगिक दृष्टिकोण जुड़ गया है। अनुसूचित जाति-जनजाति समुदायों के लिए लक्षित योजनाएं और सार्वभौमिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं इसे एक मानव-केंद्रित शासन मॉडल बनाती हैं। यही समावेशन केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की सफलता का भी आधार है। भारत के सुरक्षित भविष्य के लिए यह मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाना चाहिए। रिपोर्ट ने जो सुझाव दिए हैं उनमें राज्य जलवायु लचीलापन कोष, हर जिले में जलवायु जोखिम मानचित्रण, हरित उद्योगों और कृषि-वानिकी को बढ़ावा तथा डिजिटल तकनीक द्वारा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली हैं। हिमाचल का अनुभव बताता है कि पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन, बागवानी और जैविक खेती न केवल रोजगार दे सकते हैं बल्कि पारिस्थितिकी की रक्षा भी करते हैं। इसे सिक्किम, मेघालय और नागालैंड जैसे राज्यों ने सफलतापूर्वक अपनाया है। भारत जब सतत विकास लक्ष्यों और 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तब मानव विकास और जलवायु अनुकूलन का एकीकरण नीति का मुख्य आधार होना चाहिए। हिमाचल की नीतियां, जो सामाजिक कल्याण को पर्यावरणीय आचार-संहिता से जोड़ती हैं, अन्य राज्यों के लिए आदर्श बन सकती हैं। केंद्र सरकार की मिशन लाइफ पहल तभी सार्थक होगी जब हिमाचल जैसे राज्यों के उदाहरण उसे जमीनी ताकत दें। हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025 बताती है कि शिक्षा, समानता और पर्यावरण-संवेदनशील शासन के सहारे सीमित संसाधनों में भी चमत्कारिक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

प्रेरणा

जीन हार्पर की अदम्य हिम्मत और अटूट विश्वास की कहानी

नॉर्थ कैरोलिना के एक छोटे-से ग्रामीण इलाके में सुबह का सूरज जब धान के खेतों पर अपनी पहली किरणें बिखेरता था, तब एक मासूम बच्ची उन सुनहरी किरणों के बीच आसमान को निहारती थी। वह बच्ची थी जीन हार्पर। उसके पिता एक छोटे किसान थे, जो दिन-रात मेहनत करते थे ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। घर में सुख-सुविधाएँ नहीं थीं, लेकिन उस घर की हवा में सपनों की खुशबू तैरती थी। जीन हर दिन खेतों से लौटते समय ऊपर उड़ते पंछियों को देखती और सोचती — “काश, मैं भी एक दिन आसमान में उड़ सकूं।” उसके मन में जहाजों और उड़ानों के दृश्य बसने लगे थे। वह जानती थी कि उसका सपना बाकी बच्चों से अलग है, पर उसे यह नहीं पता था कि यही अलगपन एक दिन उसे इतिहास में दर्ज कर देगा।

जीन की उम्र उस वक्त मुश्किल से आठ साल रही होगी जब उसने पहली बार खुलकर कहा कि वह पायलट बनना चाहती है। स्कूल की तीसरी कक्षा में एक दिन शिक्षिका ने पूछा, “बच्चो, बताओ, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?” जीन ने बिना सोचे झट से जवाब दिया — “मैं हवाई जहाज उड़ाऊँगी।” यह सुनते ही पूरी कक्षा खिलखिला उठी। कुछ बच्चों ने मजाक उड़ाया और शिक्षिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, “जीन, यह कोई हकीकत नहीं, यह तो एक परियों की कहानी है। महिलाएँ पायलट नहीं बनतीं, बेटा।” उन शब्दों ने मासूम जीन के दिल में गहरी चोट छोड़ दी। उसने पहली बार यह महसूस किया कि दुनिया महिलाओं के सपनों को उतनी गंभीरता से नहीं लेती। वह चुप हो गई, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके सपनों के पंख जैसे किसी ने काट दिए हों।

दिन बीतते गए, लेकिन उस एक वाक्य ने उसे भीतर तक बदल दिया। उसने अपने मन का सपना दबा दिया। अब जब भी कोई उससे पूछता कि वह क्या बनना चाहती है, तो वह कहती — “मुझे नहीं पता।” उस उम्र में जहां बच्चे सपनों के रंगीन संसार में खोए रहते हैं, जीन का संसार अचानक स्याह हो गया था।

फिर एक दिन, जब वह हाईस्कूल में थी, उसकी नई अंग्रेज़ी शिक्षिका डोरोथी स्लेटन ने कक्षा को एक छोटा-सा असाइनमेंट दिया — “लिखो कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो।” जीन ने पेन उठाया, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। दिमाग में वही पुरानी टीचर की आवाज गूंज रही थी — “महिलाएं पायलट नहीं बन सकतीं।” उसने गहरी सांस ली और धीरे-धीरे लिखा — “मैं वेट्रेस बनना चाहती हूँ।” जब उसने कागज़ टीचर को सौंपा, तो उसके भीतर कुछ मर-सा गया।

अगले दिन डोरोथी स्लेटन ने सभी पेपर पढ़े। उन्होंने पूरी कक्षा से कहा, “मुझे लगता है कि तुम सबने सच्चे दिल से नहीं लिखा। सोचो — अगर तुम्हें किसी भी डर की परवाह न हो, अगर कोई यह न कहे कि तुम नहीं कर सकतीं — तो तुम क्या बनना चाहोगे?” ये शब्द किसी जादू की तरह जीन के भीतर उतरे। उसके मन के कोने में जो सपना सालों से दबा हुआ था, उसने सिर उठाया। उसने पेंसिल उठाई और बिना झिझक लिखा — “मैं पायलट बनना चाहती हूँ।”

डोरोथी ने जब उसका जवाब पढ़ा, तो उन्होंने मुस्कराकर कहा, “याद रखो, जीन, अगर तुम्हारे भीतर जुनून है और तुम उस सपने को दीवानगी की हद तक चाहती हो, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।” वह वाक्य जीन के जीवन का मोड़ बन गया। पहली बार किसी ने उसके सपने को स्वीकार किया था, पहली बार किसी ने उसमें विश्वास जगाया था।

इसके बाद जीन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी पढ़ाई में पहले से कहीं अधिक ध्यान देना शुरू किया। हर दिन वह आसमान की ओर देखती और खुद से कहती — “एक दिन मैं भी उड़ूंगी।” पैसे की कमी, संसाधनों की दिक्कत और समाज की पुरानी सोच उसके रास्ते में थीं, लेकिन उसके संकल्प के आगे हर दीवार कमजोर पड़ने लगी।

वर्षों की कठिन मेहनत और अथक संघर्ष के बाद वह दिन आया जब जीन हार्पर ने अपनी पहली उड़ान भरी। वह उस क्षण को कभी नहीं भूल पाई जब उसके हाथ में जहाज का नियंत्रण था और उसके नीचे फैला था असीम आसमान। वह अब प्राइवेट पायलट बन चुकी थी। यह केवल एक पेशेवर उपलब्धि नहीं थी — यह उन सारे तानों, मजाकों और अस्वीकारों का जवाब था जो उसने बचपन से सुने थे।

पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जीन ने खुद को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का फैसला किया। उसने उन्नत प्रशिक्षण लिया और 1978 में यूनाइटेड एयरलाइन्स ने इतिहास रचा — कंपनी ने पहली बार तीन महिला पायलटों को नियुक्त किया, और उन तीनों में से एक थीं जीन हार्पर। वह धीरे-धीरे बोइंग 737 की कप्तान बन गईं। एक ऐसा मुकाम, जिसकी कल्पना भी उस समय किसी महिला के लिए असंभव मानी जाती थी।

जीन ने साबित कर दिया कि सपनों की कोई जेंडर सीमा नहीं होती। उन्होंने उस सोच को तोड़ दिया जिसने कहा था कि “यह काम महिलाओं के लिए नहीं है।” उनकी उड़ान सिर्फ आसमान तक नहीं थी, बल्कि उस सीमित सोच के पार थी जो औरतों को धरती तक सीमित करना चाहती थी।

आज जीन हार्पर का नाम सिर्फ एविएशन इतिहास में दर्ज नहीं है, बल्कि वह उन सभी लोगों के दिलों में है जो कभी किसी की बातों से टूट गए, जिन्होंने अपने सपनों को किसी के शब्दों में दफना दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हकीकत वही बनती है जिस पर हम भरोसा करते हैं।

जीन ने हमें यह दिखाया कि जब इंसान अपने सपने को “जुनून” बना लेता है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। उन्होंने यह साबित किया कि उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं, विश्वास से होती है। और जब विश्वास सच्चा हो — तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है।

आतंक का पाठ पढ़ने वाले डॉक्टर, अब सम्मानित पेशे वाले भी आतंकी बन रहे

राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास जिस कार में भीषण धमाका हुआ और जिसके चलते दस से अधिक लोग मारे गए, उसका चालक भी एक डाक्टर ही निकला। नाम है उमर मोहम्मद। उसने विस्फोटक से लैस कार के साथ या तो खुद को उड़ा लिया या फिर किसी गफलत में धमाका कर बैठा। पुलवामा का उमर उन तीन डाक्टरों का सहयोगी निकला, जिनके पास से फरीदाबाद में करीब 3000 किलो विस्फोटक और हथियार मिले थे।

इनमें एक का नाम डाक्टर मुजम्मिल है और दूसरे का डाक्टर आदिल। दोनों कश्मीर के हैं। इनकी तीसरी साथी डाक्टर शाहीन है। शाहीन लखनऊ की है। इनके और साथियों की भी तलाश की जा रही है। हैरानी नहीं कि उनके संपर्क में और भी ऐसे डाक्टर निकलें, जो आतंकी हों। इन डाक्टरों के अतिरिक्त एक अन्य डाक्टर मोहिउद्दीन गुजरात पुलिस की गिरफ्त में है। उसने चीन से मेडिकल की पढ़ाई की है। उसे गुजरात पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने उसके दो साथियों के साथ हथियारों संग गिरफ्तार किया। वह अरंडी के बीज से बेहद घातक जहर राइसिन बनाने की तैयारी कर रहा था, ताकि एक साथ तमाम लोगों को मारा जा सके।

यह पहली बार नहीं है जब किसी आतंकी साजिश और घटना में किसी डाक्टर का नाम सामने आया हो। इसके पहले भी कई डाक्टर आतंक की राह पर चलते पकड़े जा चुके हैं। हाल के समय में इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम पुणे के डाक्टर अदनान अली सरकार का था। उसे एनआइए ने 2023 में गिरफ्तार किया था। वह शहर का प्रतिष्ठित डाक्टर था, लेकिन खूंखार आतंकी समूह आइएस के लिए काम कर रहा था। बीते वर्षों में डाक्टरों के अलावा कई ऐसे आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जो इंजीनियर थे।

इनमें से एक बेंगलुरु में बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहा था और शामी विटेनस नाम से आनलाइन सक्रिय रहकर मुस्लिम युवाओं को आइएस में भर्ती के लिए उकसाता भी था और उन्हें सीरिया भेजने में मदद भी करता था। डाक्टरों और इंजीनियरों के अलावा अन्य तमाम उच्च शिक्षित मुस्लिम युवा आतंकी के रूप में पकड़े जा चुके हैं। कुछ इसलिए नहीं पकड़े जा सके, क्योंकि वे पुलिस के हत्थे चढ़ने के पहले आइएस या अलकायदा का हाथ बंटाने सीरिया और अफगानिस्तान पहुंच गए। अब ऐसे पढ़े-लिखे और यहां तक कि उच्च शिक्षित युवाओं की गिनती करना कठिन है, जो आतंकी बन गए।

यह धारणा नितांत मिथ्या सिद्ध हो चुकी है कि अशिक्षित अथवा गरीब ही मजहबी उन्माद से ग्रस्त होकर या फिर किसी प्रताड़ना के चलते आतंकी बनते हैं। पिछले दो-तीन दशकों में देश और दुनिया में न जाने कितने ऐसे मुस्लिम युवकों ने आतंकी बनना पसंद किया है, जो उच्च शिक्षित थे। दुनिया भर से ऐसे युवाओं को सबसे अधिक आकर्षित किया आइएस ने। भारत में केरल से लेकर कश्मीर तक में अनेक पढ़े-लिखे मुस्लिम युवा आतंकी बन चुके हैं। पहले उनके बारे में ऐसी खबरें आती थीं कि वे किसी जिहादी मौलवी-मौलना के संपर्क आए और आतंकी बन गए। फिर ऐसी खबरें आने लगीं कि वे इंटरनेट पर जिहादी सामग्री देखकर आतंकी बन गए। कुछ तो मजहबी उन्माद से इतना अधिक भर गए कि उन्होंने गजवा ए हिंद या ऐसे ही किसी नाम से खुद का आतंकी गुट बना लिया। क्या यह किसी से छिपा है कि ऐसे नामों की प्रेरणा मजहबी मान्यताओं से ही मिलती है?

मोडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए आतंकी बनना पसंद करने वालों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे प्रताड़ित थे या फिर आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। वे चाहते तो खुशहाल जिंदगी जीते रह सकते थे, लेकिन उन पर आतंकी बनने का भूत सवार हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब इस कथन में नहीं खोजा जा सकता कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। इस कथन को लेकर सदैव विवाद होता रहता है, लेकिन इसमें तो कोई विवाद ही नहीं कि मजहब की आड़ लेकर या फिर उसके सहारे ही आतंक के रास्ते पर चला जाता है। दुनिया भर के जिहादी गुट मजहबी मान्यताओं से ही लैस हैं। इन्हीं के सहारे वे अपनी जिहादी हरकतों को सही ठहराते हैं। उनके खिलाफ समय-समय पर फतवे जारी होते रहे हैं, लेकिन अब डाक्टरों, इंजीनियरों के भी आतंकी बनने से यही सिद्ध होता है कि वे प्रभावी नहीं साबित हो रहे हैं।

जिहादी आतंक एक विचारधारा की उपज है। इस खतरनाक विचारधारा से अकेले पुलिस, खुफिया एजेंसियां और सरकारें नहीं निपट सकतीं। उससे निपटना सरकारों के साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। समाज इस जिम्मेदारी का निर्वहन तभी कर सकता है, जब वह यह समझेगा कि समस्या उन मजहबी सिद्धांतों और मूल्यों-मान्यताओं में है, जिनकी बड़ी आसानी से मनचाही व्याख्या कर ली जाती है। जिहादी आतंक से निपटने के लिए यह भी आवश्यक है कि सस्ती और संकीर्ण राजनीति न हो। दिल्ली में धमाका होते ही बिहार में मतदान के दूसरे चरण का उल्लेख करके चटखारे लेकर यह कहा जाने लगा, पता करो कहीं चुनाव हैं क्या? ऐसी छिछली बातें आतंकियों और उनके समर्थकों की ही मदद करती हैं। देश के किसी न किसी हिस्से से पुलिस की ओर से रह-रहकर किसी आतंकी माड्यूल का भंडाफोड़ करने, आतंकियों को गिरफ्तारी करने और उनके पास से विस्फोटक-हथियार बरामद करने की खबरें आती ही रहती हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आतंकी खतरा कम हो रहा है। सच यह है कि वह दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब सम्मानित पेशे वाले भी आतंकी बन रहे हैं।

अभियान

रोटी से जुड़ी ये छोटी–छोटी गलतियाँ बना सकती हैं जीवन को अशुभ, जानिए वास्तु और ज्योतिष के अनुसार सही नियम

भारतीय संस्कृति में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्म माना गया है। खासकर रोटी, जिसे अन्न का सबसे शुद्ध रूप कहा गया है, उसे बनाते समय अगर कुछ सावधानियाँ न बरती जाएँ तो उसका सीधा प्रभाव घर की खुशहाली, धन–समृद्धि और पारिवारिक वातावरण पर पड़ता है। हमारे घरों में बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि “रोटी सिर्फ आटे और पानी से नहीं बनती, उसमें घर की नीयत और ऊर्जा भी घुलती है।” लेकिन आज के आधुनिक जीवन में हम इन नियमों को नज़रअंदाज़ कर बैठे हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में रोटी से जुड़ी ऐसी कई बातें कही गई हैं, जो अगर ध्यान में रखी जाएँ तो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। कहा गया है कि रोटी बनाते समय कभी भी उसे गिनकर नहीं बनाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में रोटी गिनकर बनाई जाती है, वहां लक्ष्मी स्थिर नहीं रहतीं। धीरे-धीरे उस घर में धन की कमी और कलह बढ़ने लगती है। रोटी अन्न का प्रतीक है, और अन्न को गिनना अभाव की मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए हमेशा सहजता और श्रद्धा से रोटी बनानी चाहिए, न कि संख्या देखकर। दूसरी बड़ी भूल जो अक्सर महिलाएं कर बैठती हैं, वह है आटा गूंथते समय उस पर उंगलियों के निशान छोड़ देना। यह निशान पिंड के समान प्रतीत होते हैं, और शास्त्रों में इसे दोषकारक माना गया है। कहा गया है कि ऐसे आटे से बनी रोटी में नकारात्मक ऊर्जा समा जाती है और यह घर में क्लेश का कारण बन सकती है। इसलिए जब भी आटा गूंथें, उसे साफ-सुथरे मन से और बिना निशान छोड़े तैयार करें। हमारे पूर्वजों ने एक और सुंदर परंपरा बनाई थी — पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाने की। यह केवल आस्था नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन का भी माध्यम है। गाय को माता का स्वरूप माना गया है। वहीं, आखिरी रोटी कुत्ते को देने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं और राहु–केतु के दोष शांत होते हैं। जो परिवार इस नियम को निभाते हैं, उनके घर में अन्न और धन दोनों की कभी कमी नहीं होती। अक्सर लोग रोटी बनाने के बाद तवा उल्टा करके रख देते हैं। यह छोटी-सी आदत वास्तु दोष उत्पन्न करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि तवा उल्टा रखना पाप समान है, क्योंकि यह रसोई की ऊर्जा को बाधित करता है। उल्टा रखा हुआ तवा घर में झगड़े और रोगों को आमंत्रित करता है। इसलिए हर बार तवा साफ करके सीधा रख देना चाहिए, ताकि रसोई की ऊर्जा शुद्ध बनी रहे। एक और रोचक नियम यह है कि किसी की थाली में कभी भी तीन रोटियाँ एक साथ नहीं परोसनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में तीन का अंक राहु का प्रतिनिधित्व करता है, जो भ्रम, कलह और असंतुलन का प्रतीक है। ऐसा करने से घर के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं और खाने वाले व्यक्ति की सेहत पर भी विपरीत असर पड़ता है। इसी कारण रोटी हमेशा एक या दो, या फिर चार की संख्या में परोसी जाती है, लेकिन तीन कभी नहीं। इसके अलावा, रोटी हमेशा प्लेट या थाली में रखकर ही परोसनी चाहिए। हाथ में रोटी देना अशुभ माना गया है। यह व्यवहार न केवल अशिष्टता दर्शाता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी बाधित करता है। भोजन हमेशा आदर और पवित्रता के साथ दिया और ग्रहण किया जाना चाहिए। इन सभी नियमों का सार यही है कि भोजन केवल शारीरिक पोषण का साधन नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी आधार है। रोटी बनाना एक साधना की तरह माना गया है, जहाँ हर क्रिया — आटा गूंथने से लेकर रोटी सेंकने तक — श्रद्धा, स्वच्छता और सकारात्मक भावना से जुड़ी होती है। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं, उनके घर में अन्न की बरकत, परिवार में प्रेम और जीवन में स्थिरता बनी रहती है। लेकिन जो इन्हें नजरअंदाज करते हैं, उनके जीवन में धीरे-धीरे तनाव, आर्थिक कठिनाई और असंतोष पनपने लगता है। इसलिए अगली बार जब भी आप रोटी बनाने बैठें, तो याद रखें — यह केवल एक भोजन नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रसाद है। इसे श्रद्धा और शुद्ध मन से बनाइए, नियमों का पालन कीजिए, और देखिए कैसे आपके जीवन में सुख–शांति और समृद्धि का प्रवाह बढ़ता चला जाएगा।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में नोटरी के रूप में चयनित 1500 से अधिक अधिवक्ताओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए, नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया

गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा विधि राज्य मंत्री श्री कौशिक वेकरिया सहभागी हुए

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- कानूनी प्रक्रिया में कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी तथा ऑनेस्टी स्थापित कर विकास को गति देने में नोटरी की भूमिका महत्वपूर्ण है
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'जस्टिस टु ऑल, अपीजमेंट टु नन' मंत्र साकार हो रहा है
- सरकारी सेवाएँ सुदूरवर्ती नागरिक तक मोबाइल के एक क्लिक से पहुँचाने का प्रधानमंत्री का लक्ष्य

दस्तावेज अपलोड करने तथा आवेदन का स्टेटस जानने की समग्र प्रक्रिया अब ऑनलाइन, समय एवं शक्ति की बचत से कार्यक्षमता बढ़ेगी

नोटरी की समग्र कार्यवाही का चरणबद्ध डिजिटलाइजेशन होने से पर्यावरण की रक्षा होगी, पेपरलेस गवर्नेंस को वेग मिलेगा

गुजरात के इतिहास में पहली बार 1500 से अधिक अधिवक्ताओं को नोटरी के रूप में नियुक्ति दी गई : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के विधि विभाग तथा गुजरात बार काउंसिल के संयुक्त उपक्रम से नोटरी (लेख्य प्रमाणक) के रूप में चयनित 1500 से अधिक अधिवक्ताओं को बुधवार को गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रमाणपत्र प्रदान किए।

श्री पटेल ने राज्य में ई-नोटरी सिस्टम विकसित करने के लिए नोटरी पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साधारण व्यक्ति के हित को तथा उसकी सरलता को ईज ऑफ लिविंग के केन्द्र में रखा है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया या याजोनाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता के साथ मैक्सिमम गवर्नेंस-मिनिमम गवर्नमेंट का शासन मंत्र अपनाया है। यह कार्यक्रम गुजरात के विधि जगत में आज उसी मंत्र को साकार करने वाला अवसर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र या राज्य के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विधि (कानून) का शासन महत्वपूर्ण नींव है। प्रधानमंत्री ने कानून के शासन के लिए समयानुरूप कानून प्रस्तुत करने का भगीरथ कार्य किया है। उन्होंने अंग्रेजों के समय के अनावश्यक कानूनों को निरस्त कर कानूनी प्रक्रिया सरल बनाई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'जस्टिस टु ऑल, अपीजमेंट टु नन' मंत्र साकार हो रहा है। ट्रिपल तलाक निषेध, धारा 370 निर्मूलन तथा भारतीय न्याय संहिता का सुचारु कार्यान्वयन उनके मार्गदर्शन में हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैधानिक प्रक्रिया में विश्वास, सुरक्षा तथा प्रामाणिकता स्थापित कर विकास को गति देने में नोटरी के रूप में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री पटेल ने जोड़ा कि वैधानिक प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास का निर्माण करने के लिए दस्तावेजों की ऑथेंटिसिटी का दायित्व नोटरी के सिर होता है। नोटरी द्वारा नोटराइज किए गए दस्तावेजों को कानूनी मान्यता मिलती है तथा कोर्ट एवं अन्य स्थानों पर इन दस्तावेजों की स्वीकृति सरल बनने से लोगों का ईज ऑफ डूइंग भी बढ़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में आम आदमी को मिलने वाली सेवा सुविधाओं में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नया युग शुरू करवाया है। सरकारी सेवाएँ सुदूरवर्ती नागरिक तक मोबाइल के एक क्लिक से पहुँचाने का प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है। उन्होंने डिजिटल भारत अंतर्गत डिजिटल माध्यमों से सरकारी सेवाओं की पारदर्शी पहुँच को सुनिश्चित किया है। उनके दिशादर्शन में वैधानिक व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन पर बल दिया गया है।

उन्होंने नोटरी पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि आज गुजरात में शुरू हुआ नोटरी पोर्टल प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत के सपने को साकार करने वाला एक और कदम है। नए पोर्टल के फलस्वरूप नोटरी की नियुक्ति तथा आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। सभी को समान एवं न्यायी अवसर भी मिलेंगे। दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन का स्टेटस जानने की समग्र प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे नोटरी की सेवा लेने में लगने वाले समय एवं शक्ति की बचत से कार्यक्षमता बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि नोटरी पोर्टल से लीगल डॉक्यूमेंट भविष्य में सुरक्षित एवं प्रमाणित करने के साथ वर्षों तक उनका सेंट्रल रिकॉर्ड संरक्षित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि नोटरी की समग्र कार्यवाही का चरणबद्ध ढंग से डिजिटलाइजेशन होने से कागज का उपयोग घटेगा व पर्यावरण की रक्षा होगी, जिससे पेपरलेस गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को वेग मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने नवनियुक्त नोटरी के रूप में चयनित अधिवक्ताओं को अभिनंदन देते हुए कहा कि गुजरात के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में यानी 1500 से अधिक अधिवक्ताओं को नोटरी बनाने का भगीरथ कार्य मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

श्री संघवी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गुजरात में नोटरी के 2900 पदों की संख्या दुगुनी करके आज 6000 की गई है, जिससे भविष्य में बड़ी संख्या में वकीलों को इसका लाभ मिलेगा। आज नोटरी के लिए ई-पोर्टल राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस ई-पोर्टल के माध्यम से साधारण नागरिकों के समय की बचत होगी। उन्होंने अधिवक्ताओं से मुवक्किल के हित के साथ समाज के हित का भी ध्यान रखते हुए तेजी से न्याय दिलाने के लिए सहयोग देने की अपील की।

उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वे गौहत्या नियंत्रण तथा गौमाता रक्षा के लिए जिस कानून को लाए, वह ऐतिहासिक निर्णय था। इस अधिनियम के क्रियान्वयन से कल एक ऐतिहासिक फैसला आया। अमरेली में गौहत्या करने वाले को इस अधिनियम के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा हुई है, जो श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में लाए गए कड़े कानून का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि गुजरात में पोक्सो के मामलों में 24 घण्टों के भीतर चार्जशीट फाइल करने में सफलता मिली है। एक महीने में 15 से अधिक मामलों में चार्जशीट हुई, जिसमें कइयों को फाँसी तथा आजीवन कारावास की सजा हुई है।

विधि राज्य मंत्री श्री कौशिक वेकरिया ने कहा कि नोटरी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कानूनी प्रक्रिया में विश्वास स्थापित करने वाले हैं। नोटरी के कार्य से ठगी होने की आशंकाओं में कमी आती है। नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों को कानूनी मान्यता मिलती है। उचित ढंग से तथा योग्य पक्षकार द्वारा जब दस्तावेज बनाए जाते हैं, तब नोटरी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विशेषकर; संपत्ति के दस्तावेजों, बिक्री आदि दस्तावेजों में नोटरी के हस्ताक्षर-मुहर से कानूनी प्रक्रिया आसान बनती है। आज जब लगभग 1500 नोटरियों को एक साथ नियुक्ति मिली है, तब लोगों की सुविधा में वृद्धि होगी। नोटरी द्वारा पारदर्शी ढंग से ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा भी लोगों को कानूनी सुविधाएँ प्राप्त करने में सरलता रहेगी। इसके साथ श्री वेकरिया ने नवनियुक्त नोटरियों से लोगों के नोटरी पर रहे विश्वास को बनाए रखने की अपील की।

प्रारंभ में स्वागत संबोधन में बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री जे. जे. पटेल ने कहा कि देश में बार काउंसिल की सहायता करने का प्रारंभ गुजरात में 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 करोड़ 23 लाख रुपए का अनुदान देकर तथा ई-लाइब्रेरी की सुविधा के माध्यम से किया था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए गुजरात सरकार ने बार काउंसिल को विभिन्न कामकाज के लिए अब तक 28 करोड़ रुपए की भारी राशि की सहायता दी है। दूसरी ओर हाल ही में केन्द्र सरकार ने 8086 अधिवक्ताओं को नोटरी की उपाधि से सम्मानित किया, जबकि आज राज्य सरकार द्वारा और 1500 वकीलों को नोटरी प्रमाणपत्र दिए जाने से अब राज्य में कुल 9500 अधिवक्ता गुजरात के नोटरी के रूप में नियुक्त हुए हैं, जिसका सीधा प्रभाव जनता के कार्यों में आसानी से देखने को मिल रहा है। आज हर गाँव में जन सेवा के लिए नोटरी उपलब्ध है।

इस समारोह में मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास, संयुक्त सचिव श्री एच. एस. वर्मा, महाधिवक्ता श्री कमल त्रिवेदी, गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (जीएनएलयू) के पंजीयक श्री नितिन मलिक तथा बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।

अमूमन आम आदमी को बड़ी राहत: अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर घटकर 0.25 प्रतिशत पर पहुंची

(जीएनएस)। नई दिल्ली। महंगाई के लगातार बढ़ते दबाव के बीच आम जनता को राहत देने वाली खबर सामने आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2025 में खुदरा महंगाई दर (Consumer Price Index आधारित) घटकर 0.25 प्रतिशत पर आ गई है, जो पिछले कई वर्षों में सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट मुख्य रूप से माल एवं सेवा कर (GST) दरों में कटौती, सब्जियों और फलों की कीमतों में नरमी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की महंगाई में संतुलन के कारण हुई है। तुलना करें तो अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई दर 6.21 प्रतिशत थी, जबकि सितंबर 2025 में यह 1.44 प्रतिशत पर थी। अक्टूबर 2025 में इस दर में 119 आधार अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह वर्तमान सीपीआई श्रृंखला का सबसे निचला स्तर बन गया। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, यह संकेत है कि देश में मुद्रास्फीति का दबाव फिलहाल कम हुआ है और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीदना आसान हुआ है। खाद्य महंगाई पर नजर डालें तो अक्टूबर 2025 में यह घटकर 5.02 प्रतिशत पर पहुंच गई। एनएसओ ने बताया कि तेल, वसा, अनाज, अंडे, सब्जी और फलों की कीमतों में गिरावट, परिवहन व संचार की लागत में संतुलन और अनुकूल आधार प्रभाव के कारण कुल महंगाई दर में यह गिरावट आई है। GST दरों में कटौती का भी सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ा, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों में नरमी देखने को मिली।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति आर्थिक गतिविधियों के लिए भी अनुकूल है। उपभोक्ता खरीदारी के प्रति उत्साहित होंगे, जिससे बाजार में मांग बनी रहेगी और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, कई विश्लेषक यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि मौसमी बदलाव और वैश्विक कच्चे तेल व खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण भविष्य में महंगाई में बढ़ोतरी संभव है।

सरकारी और निजी संस्थानों के अनुसार, यह वर्तमान स्थिति उपभोक्ताओं के लिए एक संयोग है कि बाजार में जरूरी वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में हैं। इस दौर में घरेलू अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने और नागरिकों की खरीद क्षमता को बनाए रखना मुख्य चुनौती है। आने वाले महीनों में इस दर पर नजर रखी जाएगी, ताकि यदि कोई बदलाव आए तो समय रहते नीतिगत कदम उठाए जा सकें। इस डेटा के प्रकाश में आम आदमी को राहत मिली है, क्योंकि कई सालों के बाद जीवनावश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता और महंगाई में गिरावट देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह रुझान लगातार बना रहे तो उपभोक्ता खर्च और आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे देश की समग्र आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी।

प्रतापनगर यार्ड में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के विश्वामित्री – डभोई सेक्शन में स्थित प्रतापनगर स्टेशन पर यार्ड रिमोडलिंग कार्य हेतु इंजीनियरिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण 14 नवम्बर 2025 को कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। जिसका विवरण इस प्रकार हैः

पूर्णतः रद्द ट्रेनें

1. ट्रेन नं 69201 प्रतापनगर - एकतानगर मेमू ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
2. ट्रेन नं 69202 एकतानगर – प्रतापनगर मेमू ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
3. ट्रेन नं 69203 प्रतापनगर - एकतानगर मेमू ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
4. ट्रेन नं 69204 एकतानगर – प्रतापनगर मेमू ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
5. ट्रेन नं 69205 प्रतापनगर - एकतानगर मेमू ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
6. ट्रेन नं 69206 एकतानगर – प्रतापनगर मेमू ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
7. ट्रेन नं 59117 प्रतापनगर – छोटाउदैपुर पैसेंजर ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
8. ट्रेन नं 59122 छोटाउदैपुर - प्रतापनगर पैसेंजर ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
9. ट्रेन नं 59125 प्रतापनगर – छोटाउदैपुर पैसेंजर ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
10. ट्रेन नं 59126 छोटाउदैपुर - प्रतापनगर पैसेंजर ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
11. ट्रेन नं 59123 प्रतापनगर – जोबट पैसेंजर ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी
12. ट्रेन नं 59124 जोबट - प्रतापनगर पैसेंजर ट्रेन 14 नवम्बर को रद्द रहेगी

आंशिक रूप से रद्द

1. 14 नवम्बर 2025 को ट्रेन नं 59118 अलीराजपुर – प्रतापनगर पैसेंजर डभोई तक चलेगी तथा डभोई – प्रतापनगर के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।
2. 14 नवम्बर 2025 को ट्रेन नं 59121 प्रतापनगर - अलीराजपुर पैसेंजर डभोई से चलेगी तथा प्रतापनगर - डभोई के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

रेल यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

13-14 नवंबर की रात में 4 घंटे के लिए रांधेजा स्थित रेलवे फाटक नं. 15 सड़क यातायात हेतु बंद रहेगा

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मंडल के गांधीनगर हाईवे से मानसा के बीच स्थित रांधेजा रेलवे फाटक नं.15 दिनांक 13-14 नवंबर 2025 की रात में 4 घंटे के लिए सड़क यातायात हेतु बंद रहेगा।

आदरज मोटी-विजापुर रेलवे लाइन गेज परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित मशीन टेंपिंग कार्य हेतु गांधीनगर हाईवे से मानसा के बीच रांधेजा स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 15 दिनांक 13 नवंबर 2025 को रात्रि 23.00 बजे से 13 नवंबर 2025 को 03.00 बजे तक 4 घंटे के लिए सड़क यातायात हेतु बंद रहेगा।

2013 में तलाक के बाद से कोई संपर्क नहीं: जफर हयात

(जीएनएस)। कानपुर। दिल्ली में हुए हालिया बम धमाके के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी के नाम के सामने आने के बाद उनके पूर्व पति डॉ. जफर हयात ने पहली बार मीडिया के सामने अपनी चुप्पी तोड़ी। डॉ. हयात ने स्पष्ट किया कि 2013 में तलाक होने के बाद से उनका शाहीन से कोई भी संपर्क नहीं रहा और उन्हें उसके निजी जीवन या हाल की गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं है।

डॉ. शाहीन, जिन्हें फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, लखनऊ की रहने वाली हैं और कभी कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में कार्यरत रही थीं। जांच एजेंसियों को शाहीन के कानपुर से जुड़े कुछ सुराग मिले थे, जिसके बाद विशेष टीम ने कानपुर में उसकी जांच की।

डॉ. जफर हयात, जो वर्तमान में कानपुर के केपीएम अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं, ने बताया कि उनकी शादी 2003 में हुई थी और उनके दो बच्चे हैं। शादी के कुछ वर्षों बाद ही शाहीन विदेश—विशेषकर ऑस्ट्रेलिया या यूरोप—में बसने का दबाव डालने लगी। मतभेद बढ़ने के कारण 2013 में तलाक हुआ और तब से दोनों का कोई संपर्क नहीं रहा। उन्होंने कहा, "तलाक के बाद से न तो कोई बातचीत हुई और न ही मुलाकात। उसके निजी जीवन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे यह सुनकर गहरा आघात पहुंचा है।"

डॉ. हयात ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि शाहीन आतंकी गतिविधियों में कैसे शामिल हुई या उसके पास हथियार कैसे पहुंचे।

दिल्ली में सोमवार शाम हुए धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने कई शहरों में छापेमारी की थी। इसी कार्रवाई के दौरान डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी ने मेडिकल समुदाय में भी सनसनी फैला दी। जांच टीम अब शाहीन के नेटवर्क और संपर्कों की गहन पड़ताल में जुटी हुई है, ताकि उसके संभावित सहयोगियों और गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

महानगरी एक्सप्रेस में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' लिखे जाने से मचा हड़कंप आरपीएफ को मिला संदिग्ध लाल सूटकेस, आखिर क्या था अंदर?

(जीएनएस)। देशभर में सुरक्षा कड़ी करने के बीच मुंबई से वाराणसी जा रही महानगरी एक्सप्रेस में बुधवार को एक गंभीर घटना ने अफरा-तफरी मचा दी। ट्रेन के जनरल कोच के टॉयलेट की दीवार पर चाक से "पाकिस्तान जिंदाबाद", "बम धमाका" और "ISSI" जैसे शब्द लिखे पाए गए। यह संदेश यात्रियों ने देखा तो हड़कंप मच गया और रेलवे प्रशासन तथा सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। सूचना मिलते ही ट्रेन को पहले जलगांव और फिर इटारसी जंक्शन पर रोका गया। रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी, आरपीएफ, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड ने संयुक्त रूप से ट्रेन के सभी कोचों की बारीकी से तलाशी ली। जांच के दौरान एसी कोच बी-1 में एक लाल रंग का लावारिस सूटकेस भी मिला, जिससे सुरक्षा बलों में तत्काल अलर्ट पैदा हो गया। बम स्क्वॉड ने सूटकेस की जांच की तो इसमें केवल कपड़े और श्रीमद्भगवद्गीता मिली। बाद में यह सूटकेस एक यात्री का निकला, जिसे वह ट्रेन से उतरते समय भूल गया था। आरपीएफ ने तुरंत यात्री से संपर्क कर उसे बैग लेने के लिए इटारसी आने की पुष्टि कराई।

रेलवे कर्मचारियों ने बताया कि सफाई के दौरान टॉयलेट की दीवार पर लिखे संदेश की सूचना तुरंत जीआरपी और आरपीएफ को दी गई। चूंकि यह घटना दिल्ली में हाल ही हुए धमाके के बाद हुई, इसलिए इसे बेहद गंभीरता से लिया गया और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई। यह खबर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर तेजी से फैल गई, जिससे देशभर के रेलवे नेटवर्क में सतर्कता और बढ़ा दी गई।

आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव खरब ने स्पष्ट किया कि यह संदेश किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अफवाह फैलाने या डर पैदा करने के इरादे से लिखा गया प्रतीत होता है। जांच के दौरान ट्रेन को पिपरिया, नरसिंहपुर और जबलपुर समेत कई स्टेशनों पर रोका गया, लेकिन किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता नहीं चला। जीआरपी चौकी प्रभारी संजय चौकसे ने कहा कि बाथरूम में लिखे शब्द केवल अफवाह फैलाने की कोशिश प्रतीत होते हैं।

सुरक्षा के मद्देनजर जबलपुर स्टेशन पर 100 से अधिक जवान तैनात किए गए और स्टेशन परिसर, प्लेटफार्म और वाहन स्टैंड पर सघन जांच की गई। आरपीएफ अब हर अप-डाउन ट्रेन में नियमित पेट्रोलिंग कर रही है। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत रेलवे पुलिस को दें।

यह घटना रेलवे सुरक्षा की चुनौतियों को उजागर करती है और स्पष्ट करती है कि किसी भी छोटी चेतावनी को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी आतंकवादी साजिश को समय रहते नाकाम करने के लिए रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बेहद महत्वपूर्ण है। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया कि यात्रियों और अधिकारियों की चौकसी और समय पर कार्रवाई बड़ी दुर्घटनाओं को टाल सकती है।

बदायूं में कोर्ट का सख्त आदेश, इंस्पेक्टर को 6 महीने की ट्रेनिंग पर भेजा जाए

(जीएनएस)। बदायूं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में न्यायपालिका ने सख्ती दिखाते हुए सिविल लाइंस थाना के एक इंस्पेक्टर को छह महीने की प्रशिक्षण अवधि पर भेजने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई उस समय सामने आई लापरवाही के मामले में हुई है, जब इंस्पेक्टर ने कोर्ट के स्पष्ट आदेश का पालन नहीं किया। अपर सत्र न्यायालय की विशेष न्यायाधीश कु. रिंकू ने इंस्पेक्टर के रवैये की कड़ी निंदा की और एसएसपी को निर्देश दिए कि इंस्पेक्टर विजय बहादुर सिंह को प्रशिक्षण दिलाया जाए। मामला 21 अक्टूबर की रात का है, जब मोहल्ला आदर्शनगर निवासी मयंक सक्सेना का अपने मोहल्ले के लोगों के साथ झगड़ा हो गया। बीच-बचाव के लिए पहुंचे भाजपा मंडल अध्यक्ष गोपाल शर्मा के साथ भी मारपीट हुई। मयंक की शिकायत पर पुलिस ने आदित्य यादव, हर्षित और ऋषभ के खिलाफ जानलेवा हमला और लूट के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें सशर्त जमानत मिल गई।

हालांकि, मयंक और गोपाल ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि आरोपियों ने उनके साथ यह वारदात नहीं की थी। इसके बावजूद सिविल लाइंस थाना के इंस्पेक्टर विजय बहादुर ने नए मुकदमे के बजाय पहले से दर्ज मुकदमे में ही धाराओं की बढ़ोतरी कर दी। न्यायालय ने इसे विवेचक की लापरवाही और कानूनी प्रक्रिया के प्रति उदासीनता बताया।

विशेष न्यायाधीश कु. रिंकू ने टिप्पणी की कि निरीक्षक स्तर का अधिकारी होने के बावजूद इंस्पेक्टर ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और आदेश मिलने के तीन दिन तक कार्रवाई नहीं की। इसी कारण एसएसपी को निर्देश दिए गए कि इंस्पेक्टर को छह महीने का प्रशिक्षण दिया जाए और सीओ सिटी को अपनी निगरानी में प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही, पांच दिन के अंदर आदेश पर अमल की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया।

इस आदेश के बाद पुलिस विभाग में प्रशिक्षण और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन को लेकर सतर्कता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे आदेश न केवल पुलिस कर्मियों के कार्यशैली सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि जनता के प्रति न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और भरोसे को भी मजबूत करते हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी पर कसा शिकंजा 200 से अधिक ठिकानों पर चलाया सघन अभियान

(जीएनएस)। कुलगाम/सोपोर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक अभियान चलाया, जिसमें कुलगाम और सोपोर जिलों में 200 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। यह कार्रवाई राज्य में आतंकवाद समर्थक तंत्र और उसके जमीनी नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से की गई।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि कुलगाम जिले में पिछले चार दिनों से यह सघन अभियान लगातार जारी है। इस दौरान ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs), पूर्व मुठभेड़ स्थलों और सक्रिय या मारे गए आतंकवादियों से जुड़े 400 से अधिक ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किए गए। पुलिस ने 500 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की, जिनमें कई को निवारक कानूनों के तहत हिरासत में लेकर मट्टन (अनंतनाग) जिला जेल भेजा गया। छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और संवेदनशील सामग्री बरामद की गई है, जिनमें संगठन से जुड़े वित्तीय लेन-देन और गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड शामिल है।

पुलिस ने बताया कि फंडिंग नेटवर्क की भी गहन छानबीन की जा रही है। कुछ जमात सदस्यों को हिरासत में लेकर उनके आतंकी संगठनों और फंडिंग नेटवर्क से संभावित संबंधों की जांच की जा रही है। कुलगाम पुलिस ने स्पष्ट किया कि राज्य में आतंकवाद और उसके सहयोगी ढांचे के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पूरी सख्ती से लागू की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी तत्व को बख्शे बिना समाप्त करने की दिशा में निर्णायक कदम है। सोपोर जिले में भी पुलिस ने ज़ैंगीर और राफियाबाद क्षेत्रों में 25 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, यह

कार्रवाई विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई थी, जिनसे संकेत मिले थे कि प्रतिबंधित संगठन से जुड़े कुछ तत्व फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रहे थे। छापेमारी में डिजिटल डिवाइस, मुद्रित सामग्री और संगठन से संबंधित दस्तावेज़ जब्त किए गए हैं। पूछताछ के बाद नेटवर्क की परतें खोली जाएंगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पुलिस ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल संगठन के ठिकानों पर कब्ज़ा करना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे नेटवर्क, फंडिंग चैनल और जमीनी कार्यकर्ताओं की पूरी जानकारी जुटाना है। इसके तहत पुलिस ने इलाके के स्थानीय लोगों से भी सहयोग मांगा है ताकि आतंकवादियों के छिपने और सक्रिय होने के हर संभावित प्रयास को रोका जा सके।

मुख्य बिंदु:

- जम्मू-कश्मीर पुलिस का जमात-ए-इस्लामी पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन।
- कुलगाम और सोपोर में 200+ ठिकानों पर एक साथ छापेमारी।
- 500 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ, कई को निवारक कानूनों में जेल भेजा गया।
- आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और मुद्रित सामग्री बरामद।
- अभियान का उद्देश्य — आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई न केवल राज्य में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम है, बल्कि यह स्थानीय सुरक्षा तंत्र और खुफिया विभागों की सक्रियता और तत्परता का भी प्रमाण है। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में इस अभियान की दूसरी लहर भी शुरू की जाएगी, जिसमें नेटवर्क के सभी संभावित कनेक्शन और सहयोगी पूरी तरह बेनकाब किए जाएंगे।

यह अभियान राज्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने और आतंकवाद के फैलाव को रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

भरूच में दवा फैक्ट्री हादसा: बॉयलर फटने से भीषण आग, दो कर्मचारियों की मौत, कई घायल

(जीएनएस)। गुजरात के भरूच जिले के सायखा क्षेत्र में मंगलवार की रात एक दवा फैक्ट्री में भयंकर हादसा हुआ, जिसने इलाके में खलबली मचा दी। घटना रात करीब ढाई बजे हुई, जब फैक्ट्री में चल रहे बॉयलर में अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि फैक्ट्री की इमारत का अधिकांश हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और आग के लपटें फैलीं। आसपास के इलाकों में भी धमाके की आवाज सुनाई दी, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए।

इस हादसे में दो कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि लगभग 20 अन्य गंभीर और हल्की चोटों के साथ घायल हुए। जिलाधिकारी गौरांग मकवाना ने बताया कि अधिकांश कर्मचारी विस्फोट के तुरंत बाद बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन दो मजदूर मलबे और आग में फंस गए और उनकी जिंदा जलकर मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य में दमकल विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमों ने लगभग तीन घंटे तक लगातार मेहनत की। आग बुझाने के बाद दोनों मृतकों के शव मलबे से बरामद किए गए। घायल कर्मचारियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि घायलों की हालत स्थिर है और उन्हें मामूली चोटें या जलन आई है। फैक्ट्री के कुछ कर्मचारियों ने यह भी दावा किया कि अभी भी एक व्यक्ति लापता है, जिसकी तलाश जारी है।

प्रशासन ने बताया कि औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (DISH) के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। वे जांच कर रहे हैं कि फैक्ट्री संचालक के पास सभी आवश्यक सुरक्षा लाइसेंस मौजूद थे या नहीं, और बॉयलर की नियमित मेंटेनेंस समय पर की गई थी या नहीं। प्रारंभिक जांच के अनुसार, तकनीकी खराबी या ओवरप्रेशर के कारण बॉयलर फटने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, सही कारण फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। जिलाधिकारी गौरांग मकवाना ने मृतकों के परिवारों को हरसंभव सहायता देने और मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। यह हादसा न केवल कर्मचारियों और फैक्ट्री मालिकों के लिए बल्कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र के लिए गंभीर चेतावनी है कि सुरक्षा नियमों का पालन न करना जानलेवा साबित हो सकता है। हादसे ने औद्योगिक सुरक्षा, कर्मचारियों की सुरक्षा और समय पर तकनीकी जांच की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर किया है। क्षेत्रीय प्रशासन ने सभी फैक्ट्रियों को सतर्क रहने और आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

रायबरेली में STF की बड़ी कार्रवाई: एआरटीओ और पीटीओ समेत 11 नामजद, ओवरलोडिंग के अवैध घोटाले का खुलासा

(जीएनएस)। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और फतेहपुर जिलों में ओवरलोड ट्रकों से कथित अवैध वसूली के मामले में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में परिवहन विभाग के एआरटीओ और पीटीओ समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर लालगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें रायबरेली के एआरटीओ (प्रवर्तन) अंबुज, पीटीओ रेहाना बानो और अन्य कर्मचारियों तथा दलालों के नाम शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि यह अवैध नेटवर्क ओवरलोड ट्रकों से पैसे लेकर जांच के बिना उन्हें क्लियरेंस देता था, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। एसटीएफ इंस्पेक्टर की तहरीर पर दर्ज किए गए मुकदमे में क्षेत्राधिकारी लालगंज अमित सिंह ने कहा कि जांच के दौरान जिन अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

एसटीएफ ने इस कार्रवाई के दौरान अयोध्या निवासी दलाल मोहित को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि रायबरेली और फतेहपुर के एआरटीओ कार्यालयों से ओवरलोड ट्रकों को पैसे लेकर पास कराया जा रहा था। इस खुलासे ने यह भी दिखा दिया कि कई अधिकारी और दलाल मिलकर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। पिछले कुछ महीनों से इन जिलों में अवैध वसूली की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिन पर एसटीएफ ने गंभीरता से ध्यान दिया। जांच में पर्याप्त सबूत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना है कि इस खुलासे के बाद अन्य जिलों में भी परिवहन विभाग के अधिकारियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विभागीय स्तर पर भी आंतरिक जांच की संभावना जताई जा रही है।

इस मामले ने राज्य के परिवहन विभाग में सुरक्षा और पारदर्शिता की कमी को उजागर किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी कार्रवाई से भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सकती है, लेकिन सतत निगरानी और कड़ी कार्रवाई के बिना यह समस्या पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी। रायबरेली और फतेहपुर के इस घोटाले ने साफ कर दिया है कि सरकारी विभागों में अनुशासन और ईमानदारी की सुनिश्चितता बेहद जरूरी है।

बदरीनाथ धाम में सुरक्षा अलर्ट, असम राइफल्स तैनात, 25 नवंबर को बंद होंगे कपाट

(जीएनएस)। दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड में भी राज्य सरकार ने सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है और खासतौर पर चार धाम यात्रा के दौरान भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। इस क्रम में बदरीनाथ धाम में अब असम राइफल्स की टीम भी तैनात कर दी गई है।

उत्तराखंड के चार धामों में तीन धामों के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं और इस समय केवल बदरीनाथ धाम श्रद्धालुओं के लिए खुला है। रोजाना भारी संख्या में तीर्थयात्री यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ और संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए पुलिस ने बदरीनाथ क्षेत्र में आने-जाने वाले वाहनों की गहन जांच शुरू कर दी है। चमोली के एसपी सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि धाम की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने के लिए बम निरोधक दस्ते और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर टीम को तैनात किया गया है। इसके अलावा सात सदस्यीय विशेष सुरक्षा टीम भी बदरीनाथ पहुंच चुकी है।

बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। इस वजह से वर्तमान में यहां भक्तों की संख्या अधिक बनी हुई है। पुलिस और प्रशासन ने किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए हैं और सुरक्षा गश्त बढ़ा दी गई है।

सिर्फ बदरीनाथ ही नहीं, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल समेत सभी प्रमुख शहरों में 24 घंटे का सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस की टीमें हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली धमाके में उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के गदरपुर निवासी हर्षुल सेतिया भी घायल हो गए थे। हर्षुल, जो जनवरी में शादी करने वाले हैं, अपनी मां, छोटे भाई और मंगेतर के साथ शादी की शॉपिंग के लिए दिल्ली गए थे। कार विस्फोट की वजह से आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए, और उनके सिर में इन टूटे हुए शीशों से चोट लगी। उनका इलाज फिलहाल जारी है। बदरीनाथ धाम और पूरे राज्य में तैनात सुरक्षा बल और सघन चेकिंग अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी अप्रिय घटना न हो और श्रद्धालु सुरक्षित रूप से दर्शन कर सकें। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत सुरक्षा अधिकारियों को दें।

अलीगढ़ में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दहला दिया गांव, फावड़े से काटकर की हत्या

(जीएनएस)। अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गोंडा थाना क्षेत्र के गांव तारापुर से एक खौफनाक और सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। मंगलवार को दो भाइयों के बीच किसी मामूली कहासुनी ने अचानक भयावह रूप ले लिया और बड़े भाई विवेक सारस्वत ने अपने छोटे भाई ललित सारस्वत (20 वर्ष) की धारदार फावड़े से गर्दन काटकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा और लोगों में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों और पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना उस समय हुई जब दोनों भाइयों के बुजुर्ग पिता किशन स्वरूप सारस्वत अपनी पत्नी को दवा दिलाने शहर गए हुए थे। घर पर अकेले पड़े दोनों बेटे मामूली बहस के कारण भिड़ गए। सामान्य विवाद जल्द ही बढ़ता गया और आवेश में आया बड़ा भाई विवेक अचानक अपने छोटे भाई ललित पर फावड़े से हमला कर बैठा। वारदात इतनी तेज थी कि ललित को मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। इलाका थानाध्यक्ष, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मौके से हत्यारे बड़े भाई विवेक को हिरासत में ले लिया और वारदात में इस्तेमाल किए गए फावड़े को भी बरामद किया। इसके साथ ही, पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और सभी साक्ष्य जुटाए।

पुलिस पूछताछ में अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मामूली बहस के पीछे की असली वजह क्या थी। क्षेत्राधिकारी गोंडा महेश वर्मा ने बताया कि घटना के समय पिता और मां घर पर नहीं थे, और यही अवसर विवेक को ललित पर हमला करने का मिला। उन्होंने कहा कि पुलिस विवेक से पूरी जानकारी जुटाकर कानूनी कार्रवाई कर रही है। इस हत्याकांड ने गांव में दहशत और शोक का माहौल बना दिया है। मृतक के परिवार और ग्रामीणों ने घटना की निंदा की है और सुरक्षा के प्रति प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हत्यारे विवेक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह घटना छोटे विवादों और झगड़ों के नियंत्रित न होने का एक भयावह उदाहरण है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी और घटना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। यह वारदात समाज में एक चेतावनी भी है कि मामूली विवाद को नजरअंदाज करना या उसे हल्के में लेना कभी-कभी बड़े और अप्रत्याशित परिणाम ला सकता है।

बीरभूम का अनोखा मामला: पति ने शादी के 9 साल बाद पत्नी को दोस्त से कराई शादी, बोला- 'अब मैं आजाद'

(जीएनएस)। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से एक हैरान करने वाला और अनोखा मामला सामने आया है। यहां के सैंथिया क्षेत्र में रहने वाले बापी मंडल ने अपने नौ साल पुराने वैवाहिक जीवन को अचानक समाप्त कर दिया और इसके बाद अपनी पत्नी की शादी अपने दोस्त से करवा दी। यह घटना इतनी असामान्य थी कि इसकी जानकारी मिलते ही लोग देखने के लिए मंदिर में उमड़ पड़े।

बापी मंडल की शादी लगभग नौ साल पहले बीरभूम के तारापीठ की पंचमी मंडल से हुई थी। दोनों का एक सात साल का बेटा भी है। हालांकि शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच कलह शुरू हो गई थी और महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामला कोर्ट तक पहुंचा, और महिला अपने पिता के घर चली गई, जबकि उनका बेटा बापी के साथ रहने लगा।

समय के साथ महिला और बापी के दोस्त जीतकुमार मिर्धा के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं, जो धीरे-धीरे प्रेम में बदल गईं। जीतकुमार का घर सैंथिया के वार्ड नंबर 16 में है। जैसे ही पति बापी को इस संबंध की जानकारी मिली, उसने एक बेहद अनोखा कदम उठाया।

सोमवार सुबह बापी, अपनी पत्नी और दोस्त के साथ सैंथिया के नंदिकेशरी सतीपीठ मंदिर पहुंचा और वहां दोनों की शादी करवा दी। इस दौरान महिला ने अपने पति के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को वापस ले लिया।

मंदिर में नए शादीशुदा जोड़े के सामने खड़े होकर बापी मंडल ने कहा, "अब मैं आजाद हूं। मेरी पत्नी अब मेरे दोस्त की पत्नी है और अब से वही उसका गुजारा संभालेगा।" उन्होंने यह भी बताया कि पत्नी ने वादा किया था कि अगर वह उसे अपने दोस्त से शादी करवा देगा, तो वह अपने केस को वापस ले लेगी। यह मामला न केवल बीरभूम में चर्चा का विषय बना, बल्कि पूरे इलाके में लोगों को आश्चर्यचकित कर गया। यह घटना पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक दृष्टिकोण से अनोखी और चौंकाने वाली मानी जा रही है।

सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो जनरल हुड्डा की कार को पंजाब पुलिस की जीप ने मारी टक्कर, जांच शुरू

(जीएनएस)। पंजाब के मोहाली जिले में चंडीगढ़-अंबाला नेशनल हाइवे पर एक चौंकाने वाली घटना हुई। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डी.एस. हुड्डा की कार को जीरकपुर फ्लाईओवर पर पंजाब पुलिस की एक जीप ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि यह जीप किसी वीआईपी काफिले को एस्कॉर्ट कर रही थी। घटना के बाद पुलिस वाहन मौके से भाग गई, जबकि जनरल हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी आपबीती साझा करते हुए कार्रवाई की मांग की।

जनरल हुड्डा ने लिखा कि वह अपनी पत्नी के साथ गाड़ी चला रहे थे। ट्रैफिक की वजह से उनकी कार धीमी चल रही थी। उसी समय वीआईपी काफिले को एस्कॉर्ट कर रही पंजाब पुलिस की जीप तेज गति से आई और गुस्साए चालक ने बाईं ओर से ओवरटेक कर उनकी कार को दाहिनी ओर से जानबूझकर टक्कर मार दी। जनरल हुड्डा ने इसे पुलिस की लापरवाही और अहंकार बताया और मुख्यमंत्री तथा डीजीपी से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार न केवल वर्दी और विभाग की साख को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है।

जनरल हुड्डा के ट्वीट के बाद पंजाब डीजीपी ने भी तुरंत सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि जनरल डी.एस. हुड्डा और उनकी पत्नी को हुई असुविधा के लिए खेद है। इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है और पंजाब पुलिस के मूल्यों के खिलाफ है। डीजीपी ने स्पेशल डीजीपी ट्रैफिक ए.एस. राय से संबंधित वाहनों और तैनात पुलिसकर्मियों की पहचान कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पंजाब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना सुरक्षा और नियमों के पालन के महत्व को फिर से उजागर करती है, खासकर तब जब वर्दी और एस्कॉर्ट की जिम्मेदारी जुड़ी हो।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक, पन्ने पर लिखे गए देश-विरोधी संदेश और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आरोपों के बीच सुरक्षा जांच तेज

(जीएनएस)। फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सोमवार को हैक कर ली गई। हैकर्स ने वेबसाइट पर आपत्तिजनक संदेश पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि अगर भारत में रहना है तो शांति से रहना होगा, अन्यथा इस्लामिक जिहाद करने वालों को देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। संदेश में आगे चेतावनी दी गई कि "हम तुम्हारी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, इसे बंद करो नहीं तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे।" घटना के कुछ देर बाद ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रिस्टोर कर लिया गया।

यह घटना ऐसे समय पर सामने आई है, जब फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मिलकर हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार, डॉ. मुजम्मिल अल-फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे और यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर ही डॉक्टर्स क्वार्टर में रहते थे। वह पिछले साल से फरीदाबाद में रह रहे थे और जनरल फिजिशियन के तौर पर काम कर रहे थे।

पुलिस को डॉ. मुजम्मिल के जैश-ए-मुहम्मद से संबंधों की जानकारी मिली थी। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से एक एसॉल्ट राइफल, 83 गोलियां, दो मैगजीन, एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा दो खाली खोखे और पिस्तौल की एक मैगजीन भी पुलिस ने जब्त की।

गिरफ्तारी से 15 दिन पहले ही डॉ. मुजम्मिल के कब्जे से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। यूनिवर्सिटी से महज कुछ दूरी पर 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी पुलिस ने कब्जे में लिया था। जांच में सामने आया कि आतंकी मुजम्मिल अक्सर एक लेडी डॉक्टर की कार का इस्तेमाल करता था, जिसमें उसकी राइफल रखी जाती थी।

इस वेबसाइट हैकिंग मामले ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के सुरक्षा उपायों और ऑनलाइन साइबर सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस घटना के बाद साइबर सुरक्षा की समीक्षा शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसे किसी भी संभावित साइबर हमले को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे।